

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र/ कम्प्यूटर/बी/ आई.सी.टी./ 04/2006/ 241
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/8/06

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय:—शासकीय स्कूलों में कम्प्यूटर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए आई.सी.टी. @ स्कूल योजना के क्रियान्वयन के संबंध में ।

स्कूल शिक्षा में कम्प्यूटर का उपयोग कर शिक्षा में गुणवत्ता लायी जाए और बच्चों को कम्प्यूटर के उपयोग के बारे में जानकारी हो सके इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में "आई.सी.टी. @ स्कूल " योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत 230 विद्यालयों का चयन किया गया है । चयनित विद्यालयों की सूची संलग्न परिशिष्ट— एक अनुसार है ।

आई.सी.टी. @ स्कूल योजना भारत सरकार की केन्द्र प्रवर्तित योजना है । इस योजना की प्रति आपके अवलोकन के लिए संलग्न (परिशिष्ट - दो) है । इस योजना के तहत एक विद्यालय को 10 कम्प्यूटर पी.सी., प्रिंटर आदि उपलब्ध कराया जाना है । इसके अतिरिक्त फर्नीचर, कम्प्यूटर स्टेशनरी के लिए भी राशि उपलब्ध कराई जाएगी । एजुकेशन साफ्टवेयर, शिक्षक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था संचालनालय स्तर से की जाएगी । कम्प्यूटर तथा अन्य उपकरण क्रय करने के लिए स्पेसिफिकेशन, कन्पयूगेशन की जानकारी पृथक से भेजी जाएगी ।

इस योजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग तथा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है । राज्य स्तरीय समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि स्कूलों में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए हार्डवेयर खरीदी की विकेन्द्रिकृत व्यवस्था लागू की जाए और जिला स्तरीय समिति के माध्यम से खरीदी की कार्यवाही की जाए । स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला स्तरीय समिति के गठन के संबंध में जारी आदेश दिनांक 10.10.2005 की प्रति संलग्न (परिशिष्ट— तीन) हैं ।

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक आवंटन / राशि पृथक से जारी की जा रही है । इस योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथमतः निम्नलिखित कार्यवाही करने का अनुरोध है:—

1. जिलों के लिए चिन्हांकित स्कूलों में कम्प्यूटर लेब के लिए एक कमरा चिन्हांकित कर तथा आवश्यक मरम्मत कर उसको कम्प्यूटर लेब के योग्य बना लिया जाए । यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि सितम्बर तक कम्प्यूटर लेब पूरी तरह स्थापित हो जाए ।
2. जिला मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालयों में क्लास प्रोजेक्ट के अंतर्गत कम्प्यूटर स्थापित किए गए हैं और इन विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता का अध्यापन भी प्रारंभ किया गया । अतः इन विद्यालयों में उपलब्ध सुविधा का लाभ भविष्य में कम्प्यूटर साक्षरता की दृष्टि से भी किया जाए ।

कृपया जिला स्तरीय समिति की बैठक सर्वप्रथम आयोजित करने का कष्ट करें ताकि सभी सदस्य योजना के बारे में पूर्णतः वाकिफ हो जाए ।


(एल.एस.बघेल)

आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ. क्र/ कम्प्यूटर/बी/ आई.सी.टी./ 04/2006/ 242

भोपाल, दिनांक 12/8/06

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
 2. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
 3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
 4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


आयुक्त

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट-एक

आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित 230 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की सूची

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित विद्यालयों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	ग्वालियर	ग्वालियर	घाटीगांव	उत्कृष्ट विद्यालय, घाटीगांव
2			भितरवार	उत्कृष्ट विद्यालय, भितरवार
3			डबरा	शा.बा.उ.मा.वि., करियावटी
4			मुरार	शा.उ.मा.वि., उटीला
5		शिवपुरी	कौलारस	उत्कृष्ट विद्यालय, कौलारस
6			करैरा	उत्कृष्ट विद्यालय, करैरा
7			नरवर	उत्कृष्ट विद्यालय, नरवर
8			पोहरी	उत्कृष्ट विद्यालय, पोहरी
9			पिछोर	उत्कृष्ट विद्यालय, पिछोर
10			खनियाधाना	उत्कृष्ट विद्यालय, खनियाधाना
11			बदरवास	उत्कृष्ट विद्यालय, बदरवास
12		गुना	बामोरी	उत्कृष्ट विद्यालय, बामोरी
13			चाचौड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, चांचोड़ा
14			आरौन	उत्कृष्ट विद्यालय, आरोन
15		अशोकनगर	ईसागढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, ईसागढ़
16			मुंगावली	उत्कृष्ट विद्यालय, मुंगावली
17		दतिया	सेवड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, सेवड़ा
18			दतिया	शा.उ.मा.वि., बीकर
19			भाण्डेर	उत्कृष्ट विद्यालय, भाण्डेर
20		भिण्ड	अटेर	उत्कृष्ट विद्यालय, अटेर
21			मेहगांव	उत्कृष्ट विद्यालय, मेहगांव
22			लहार	उत्कृष्ट विद्यालय, लहार
23			रौन	उत्कृष्ट विद्यालय, मिहोना (रौन)
24		मुरैना	जौरा	उत्कृष्ट विद्यालय, जोरा
25			पहाड़गढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, पहाड़गढ़
26			कैलारस	उत्कृष्ट विद्यालय, कैलारस
27			मुरैना	शा.उ.मा.वि., बान्मोर (संशोधित)
28		श्योपुर	श्योपुरकलां	शा.उ.मा.वि., प्रेमसर
29			विजयपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, विजयपुर
30	उज्जैन	उज्जैन	महिदपुर	शा.कन्या उ.मा.वि. महिदपुर (संशोधन उपरांत संशोधित)
31			तराना	शा.उ.मा.वि., माकडोन (संशोधन उपरांत)
32			खाचरौद	शा.उ.मा.वि. कन्या, नागदा (संशोधन उपरांत)
33			उज्जैन	शा.उ.मा.वि., नरवर

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित विद्यालयों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	उज्जैन	नीमच	जावद	उत्कृष्ट विद्यालय, जावद
35			मनासा	उत्कृष्ट विद्यालय, मनासा
36		मंदसौर	सीतामऊ	शा.उ.मा.वि., करजू (संशोधित)
37			भानपुरा	शा.बा.उ.मा.वि., भैसोदा (संशोधित)
38			गरोठ	शा.बा.उ.मा.वि., शामगढ़ (संशोधित)
39			मल्हारगढ़	शा.बा.उ.मा.वि., नारायणगढ़ (संशोधित)
40		शाजापुर	मोमन बड़ौदिया	उत्कृष्ट विद्यालय, मोमन बड़ौदिया
41			बड़ोद	उत्कृष्ट विद्यालय, बड़ोद
42			सुसनेर	उत्कृष्ट विद्यालय, सुसनेर
43			नलखेड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, नलखेड़ा
44			कालापपीपल	उत्कृष्ट विद्यालय, कालापपीपल
45		रतलाम	सैलाना	उत्कृष्ट विद्यालय, सैलाना
46			बाजना	उत्कृष्ट विद्यालय, बाजना
47			पिपलौदा	उत्कृष्ट विद्यालय, पिपलौदा
48			आलोट	उत्कृष्ट विद्यालय, आलोट
49	इन्दौर	देवास	सोनकच्छ	उत्कृष्ट विद्यालय, सोनकच्छ
50			टोंकखुर्द	उत्कृष्ट विद्यालय, टोंकखुर्द
51			कन्नौद	उत्कृष्ट विद्यालय, कन्नौद
52			खातेगांव	उत्कृष्ट विद्यालय, खातेगांव
53			बागली	उत्कृष्ट विद्यालय, बागली
54		इंदौर	महू	शा.उ.मा.वि., हरसोला, महू
55			इंदौर	शा.उ.मा.वि. बालक, केम्पल
56			सांवेर	उत्कृष्ट विद्यालय, सांवेर
57			देपालपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, देपालपुर
58		धार	बदनावर	उत्कृष्ट विद्यालय, बदनावर
59			नालछा	उत्कृष्ट विद्यालय, नालछा
60			कुक्की	उत्कृष्ट विद्यालय, कुक्की
61			बाग	उत्कृष्ट विद्यालय, बाग
62			तिरला	उत्कृष्ट विद्यालय, तिरला
63			सरदारपुरा	उत्कृष्ट विद्यालय, सरदारपुरा
64		खरगौन	बड़वाहा	शा.उ.मा.वि. बलवाड़ा
65			सेगांव	उत्कृष्ट विद्यालय, सेगांव
66			भीकनगांव	उत्कृष्ट विद्यालय, भीकनगांव
67			महेश्वर	उत्कृष्ट विद्यालय, महेश्वर
68			कसरावद	उत्कृष्ट विद्यालय, कसरावद
69		बड़वानी	ठीकरी	उत्कृष्ट विद्यालय, ठीकरी
70			राजपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, राजपुर
71			निवाली	उत्कृष्ट विद्यालय, निवाली

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित विद्यालयों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
72	इन्दौर	खण्डवा	पुनासा	उत्कृष्ट विद्यालय, पुनासा
73			छेगांवमाखन	उत्कृष्ट विद्यालय, छेगांव माखन
74			पंधाना	उत्कृष्ट विद्यालय, पंधाना
75			हरसूद	उत्कृष्ट विद्यालय, छनेरा (हरसूद)
76			खालवा	उत्कृष्ट विद्यालय, खालवा
77			बलड़ी (किल्लौद)	उत्कृष्ट विद्यालय, बलड़ी (किल्लोद)
78			बुरहानपुर	बुरहानपुर
79	झाबुआ	रामा	उत्कृष्ट विद्यालय, रामा	
80		रानापुर	उत्कृष्ट विद्यालय, रानापुर	
81		सोण्डवा	उत्कृष्ट विद्यालय, सोण्डवा	
82		कट्टीवाडा	उत्कृष्ट विद्यालय, कट्टीवाडा	
83		जोबट	उत्कृष्ट विद्यालय, जोबट	
84		उदयगढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, उदयगढ़	
85		भांवरा	उत्कृष्ट विद्यालय, भांवरा	
86		पेटलावद	उत्कृष्ट विद्यालय, पेटलावद	
87		थांदला	उत्कृष्ट विद्यालय, थांदला	
88		मेघनगर	शा.उ.मा.वि., रंभापुर	
89		भोपाल	भोपाल	फंदा
90	बैरसिया			शा.उ.मा.वि., गुनगा
91	सीहोर	सीहोर	इछावर	
92		बुधनी	उत्कृष्ट विद्यालय, बुधनी	
93		नसरुल्लागंज	उत्कृष्ट विद्यालय, नसरुल्लागंज	
94	रायसेन	सांची	उत्कृष्ट विद्यालय, सांची	
95		ओबेदुल्लागंज	उत्कृष्ट विद्यालय, ओबेदुल्लागंज	
96		गैरतगंज	उत्कृष्ट विद्यालय, गैरतगंज	
97		सिलवानी	उत्कृष्ट विद्यालय, सिलवानी	
98		बरेली	उत्कृष्ट विद्यालय, बरेली	
99	उदयपुरा	उत्कृष्ट विद्यालय, उदयपुरा		
100	राजगढ़	खिलचीपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, खिलचीपुर	
101		राजगढ़	शा.क.उ.मा.वि., खुजनेर	
102		जीरापुर	उत्कृष्ट विद्यालय, जीरापुर	
103	विदिशा	नटेरन	उत्कृष्ट विद्यालय, नटेरन	
104		कुरवाई	उत्कृष्ट विद्यालय, कुरवाई	
105		ग्यारसपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, ग्यारसपुर	
106		लटेरी	उत्कृष्ट विद्यालय, लटेरी	
107	बैतूल	मुलताई	उत्कृष्ट विद्यालय, मुलताई	
108		बैतूल	शासकीय उ.मा.वि., जीन	

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित विद्यालयों के नाम	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
109	भोपाल	बैतूल	चिंचौली	उत्कृष्ट विद्यालय, चिंचौली	
110			घोड़ाडोंगरी	उत्कृष्ट विद्यालय, घोड़ाडोंगरी	
111			शाहपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, शाहपुर	
112			भैंसदेही	उत्कृष्ट विद्यालय, भैंसदेही	
113			आठनेर	उत्कृष्ट विद्यालय, आठनेर	
114			भीमपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, भीमपुर	
115			प्रभात पट्टनम	उत्कृष्ट विद्यालय, प्रभाथ पट्टनम	
116			होशंगाबाद	बावई	उत्कृष्ट विद्यालय, बावई
117				सोहागपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, सोहागपुर
118				बनखेडी	उत्कृष्ट विद्यालय, बनखेडी
119				कैसला	उत्कृष्ट विद्यालय, कैसला
120	हरदा	खिरकिया	उत्कृष्ट विद्यालय, खिरकिया		
121		टिमरनी	उत्कृष्ट विद्यालय, टिमरनी		
122		हरदा	शा.उ.मा.वि., हाण्डिया		
123	सागर	सागर	राहतगढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, राहतगढ़	
124			सागर	शा.बा.उ.मा.वि., ढाना	
125			जैसीनगर	उत्कृष्ट विद्यालय, जैसीनगर	
126			कैसली	उत्कृष्ट विद्यालय, कैसली	
127			देवरी	शा.उ.मा.वि., महाराजपुर	
128			बंडा	उत्कृष्ट विद्यालय, बंडा	
129			शाहगढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, शाहगढ़	
130			मालथौन	उत्कृष्ट विद्यालय, मालथौन	
131			बीना	शा.उ.मा.वि., मण्डीबामौरा	
132			दमोह	पथरिया	उत्कृष्ट विद्यालय, पथरिया
133				दमोह	शा.उ.मा.वि., बादकपुर
134	जबेरा	उत्कृष्ट विद्यालय, जबेरा			
135	तेन्दूखेड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, तेन्दूखेड़ा			
136	पटेरा	उत्कृष्ट विद्यालय, पटेरा			
137	बटियागढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, बटियागढ़			
138	पन्ना	पन्ना	उत्कृष्ट विद्यालय, गुनौर		
139		पवई	उत्कृष्ट विद्यालय, पवई		
140		शाहनगर	उत्कृष्ट विद्यालय, शाहनगर		
141		अजयगढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, अजयगढ़		
142	छतरपुर	राजनगर	उत्कृष्ट विद्यालय, राजनगर		
143		छतरपुर	शा.उ.मा.वि., ईसानगर		
144		नौगांव	शा.ने.उ.मा.वि., महाराजपुर		
145		लौडी	उत्कृष्ट विद्यालय, लौडी		
146		गौरीहार	उत्कृष्ट विद्यालय, गौरीहार (बारीगढ़)		

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित विद्यालयों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
147	सागर	छतरपुर	बिजावर	उत्कृष्ट विद्यालय, बिजावर
148			बड़ामलहरा	उत्कृष्ट विद्यालय, बड़ामलहरा
149			बक्सवाहा	उत्कृष्ट विद्यालय, बक्सवाहा
150		टीकमगढ़	बल्देवगढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, बल्देवगढ़
151			टीकमगढ़	शा.उ.मा.वि., निवाड़ी
152			निवाड़ी	उत्कृष्ट विद्यालय, निवाड़ी
153			पृथ्वीपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, पृथ्वीपुर
154			जतारा	उत्कृष्ट विद्यालय, जतारा
155			पलेरा	उत्कृष्ट विद्यालय, पलेरा
156	जबलपुर	जबलपुर	बरगी	शा.उ.मा.वि., तेवर
157			कुण्डम	उत्कृष्ट विद्यालय, कुण्डम
158			मझौली	उत्कृष्ट विद्यालय, मझौली
159			पाटन	उत्कृष्ट विद्यालय, पाटन
160			शहपुरा	उत्कृष्ट विद्यालय, शहपुरा
161		मण्डला	मोहगांव	उत्कृष्ट विद्यालय, मोहगांव
162			घुघरी	उत्कृष्ट विद्यालय, घुघरी
163			बिछिया	उत्कृष्ट विद्यालय, बिछिया
164			निवास	उत्कृष्ट विद्यालय, निवास
165			नारायणगंज	उत्कृष्ट विद्यालय, नारायणगंज
166			बीजाडोडी	उत्कृष्ट विद्यालय, बीजाडोडी
167		डिण्डोरी	समनापुर	उत्कृष्ट विद्यालय, समनापुर
168			शहपुरा	उत्कृष्ट विद्यालय, शहपुरा
169		कटनी	बहोरीबंद	उत्कृष्ट विद्यालय, बहोरीबंद
170			ढीमरखेड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, ढीमरखेड़ा
171			रीठी	उत्कृष्ट विद्यालय, रीठी
172			बडवारा	उत्कृष्ट विद्यालय, बडवारा
173			विजयराघवगढ़	उत्कृष्ट विद्यालय, विजय राघवगढ़
174	नरसिंहपुर		गोटेगांव	उत्कृष्ट विद्यालय, गोटेगांव
175			करेली	उत्कृष्ट विद्यालय, करेली
176			सांईखेड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, सांईखेड़ा
177			बाबई चीचली	उत्कृष्ट विद्यालय, बाबई चीचली
178			चांवरापाठा	उत्कृष्ट विद्यालय, चांवरपाठा
179		छिन्दवाड़ा	परासिया	उत्कृष्ट विद्यालय, परासिया
180			छिन्दवाड़ा	शा.उ.मा.वि., सारना
181			तामिया	उत्कृष्ट विद्यालय, जामई
182			जामई	उत्कृष्ट विद्यालय, जामई
183			बिछुआ	उत्कृष्ट विद्यालय, बिछुआ

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित विद्यालयों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
184	जबलपुर	छिन्दवाड़ा	हरई	उत्कृष्ट विद्यालय, हरई
185			मोहखेड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, मोहखेड़ा
186			सौसर	उत्कृष्ट विद्यालय, सौसर
187			अमरवाड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, अमरवाड़ा
188			चौरई	उत्कृष्ट विद्यालय, चौरई
189	सिवनी	लखनादौन	लखनादौन	उत्कृष्ट विद्यालय, लखनादौन
190			छपारा	उत्कृष्ट विद्यालय, छपारा
191			धनौरा	उत्कृष्ट विद्यालय, धनौरा
192			बरघाट	उत्कृष्ट विद्यालय, बरघाट
193			केवलारी	उत्कृष्ट विद्यालय, केवलारी
194	बालाघाट	लांजी	लांजी	उत्कृष्ट विद्यालय, लांजी
195			किरनापुर	उत्कृष्ट विद्यालय, किरनापुर
196			बिरसा	उत्कृष्ट विद्यालय, बिरसा
197			बैहर	उत्कृष्ट विद्यालय, बैहर
198			परसवाड़ा	उत्कृष्ट विद्यालय, परसवाड़ा
199			खैरलांजी	उत्कृष्ट विद्यालय, खैरलांजी
200			लालबर्गा	उत्कृष्ट विद्यालय, लालबर्गा
201			कटंगी	उत्कृष्ट विद्यालय, कटंगी
202	रीवा	रीवा	रायपुर कर्चुलियन	उत्कृष्ट विद्यालय, रायपुर कर्चुलियन
203			रीवा	शा.उ.मा.वि., डिहिया
204			मऊगंज	उत्कृष्ट विद्यालय, मऊगंज
205			हनुमना	उत्कृष्ट विद्यालय, हनुमना
206			नईगढ़ी	उत्कृष्ट विद्यालय, नईगढ़ी
207			त्योंथर	उत्कृष्ट विद्यालय, त्योंथर
208			जवां	उत्कृष्ट विद्यालय, जवां
209			सिरमौर	उत्कृष्ट विद्यालय, सिरमौर
210			गंगेव	उत्कृष्ट विद्यालय, गंगेव
211			शहडोल	ब्यौहारी
212	बुढ़ार	उत्कृष्ट विद्यालय, बुढ़ार		
213	जयसिंहनगर	उत्कृष्ट विद्यालय, जयसिंहनगर		
214	अनूपपुर	जैतहारी	उत्कृष्ट विद्यालय, जैतहारी	
215	उमरिया	उमरिया (करकेली)	उमरिया (करकेली)	शास.उ.मा.वि., कोडिया
216			मानपुर	उत्कृष्ट विद्यालय, मानपुर
217	रीवा	सीधी	सिंहावल	उत्कृष्ट विद्यालय, सिंहावल
218			मझौली	उत्कृष्ट विद्यालय, मझौली
219			रामपुर नैकिन	उत्कृष्ट विद्यालय, रामपुर नैकिन
220			देवसर	उत्कृष्ट विद्यालय, देवसर
221			चितरंगी	उत्कृष्ट विद्यालय, चितरंगी
222			बैढ़न	उत्कृष्ट विद्यालय, बैढ़न

क्र.	संभाग का नाम	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	आई.सी.टी. @ स्कूल योजना संचालन हेतु चयनित विद्यालयों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
223	रीवा	सतना	चित्रकूट	उत्कृष्ट विद्यालय, चित्रकूट (मझगंवा)
224			सतना (सुहावल)	शा.उ.मा.वि., रैगांव
225			रामपुर बधेलान	उत्कृष्ट विद्यालय, रामपुर बधेलान
226			नागोद	उत्कृष्ट विद्यालय, नागोद
227			उचेहरा	उत्कृष्ट विद्यालय, उचेहरा
228			अमरपाटन	उत्कृष्ट विद्यालय, अमरपाटन
229			अमरपाटन	शा.उ.मा.वि., मुकुन्दपुर (संशोधित)
230			मैहर	शा.उ.मा.वि., अमदरा.

“परिशिष्ट-दो”

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY@ SCHOOLS

INTRODUCTION

Information & Communication Technology (ICT) is universally acknowledged as an important catalyst for social transformation and national progress. However, disparities in the levels of ICT readiness and use could translate into disparities in level of productivities and hence could influence a country's rate of economic growth. Understanding and leveraging ICT is therefore critical for countries striving for continued social and economic progress.

India shows enormous geographic and demographic disparity in ICT use. India has one of the largest ICT workforces in the world. One can find intense ICT use in technology clusters such as Bangalore and Gurgaon or amongst the upper middle brackets of incomes. The other side of the story is that large parts of the country lack even telephone connectivity.

BACKGROUND

India recognized the importance of ICT in education as early as 1984-85 when the Computer Literacy And Studies in Schools (CLASS) Project was initially introduced as a pilot with the introduction of BBC micro-computers. A total of 12,000 such computers were received and distributed to secondary and senior secondary schools through State Governments. The project was subsequently adopted as a Centrally Sponsored Scheme during the 8th Plan (1993-98). During the 8th Five Year Plan the Scheme was widened to provide Financial grants to institutions which were given BBC Micros and also to cover new Government Aided Sec./Sr. Sec. Schools. Assistance included annual maintenance grant for BBC micros and purchase as well as maintenance of equipment for new Schools.

2598 Schools having BBC Micros were covered under the CLASS scheme during the 8th Plan for providing Instructors, maintenance of hardware, consumables and text books for students and training of teachers in schools. In additions, 2371 schools were covered with new hardware and services which included Rs. 1.00 lakh for hardware configuration and Rs. 1.30 lakhs per annum for recurring costs. Rs. 0.80 lakh per annum was kept as the recurring costs for schools which has already been covered under the BBC-Micros scheme.

NIC was identified as the nodal agency for finalising the contract for the supply of hardware. The use and supply of software was limited, coverage was confined to Sr. Secondary Schools and the students of class XI & XII had to undergo a Computer Course Module.

National Task Force on Information Technology and Software Development (IT Task Force)—constituted by the Prime Minister-in July, 1998 has made specific recommendations on introduction of I. T. in the education sector including schools. The relevant paragraphs are reproduced below:

Vidyarathi Computer Scheme, Shikshak Computer Scheme and Scheme and School Computer Scheme to enable students, teachers or schools respectively, desirous of buying computers to do so under attractive financial packages. These schemes will be supported by a suite of initiatives such as lowering the cost of PCs, easy installment bank loans, computer donations by IT companies and other business houses, bulk donations of computers by NRI organizations, large-volume bargain price imports, multi-lateral funding, etc.

Computers and Internet shall be made accessible to schools, polytechnics, colleges, and public hospitals in the country by the year 2003.

The concept of SMART Schools where the emphasis is not only on Information Technology in Schools, but also on the use of skills and values that will be important in the next millennium, shall be started on a pilot demonstrative basis in each State.

The Report recommended provision of computer systems to all educational Institutions upto Higher Secondary/ Secondary Schools by suitable investments (about 1- 3%) of the total budget during the next five years.

The recommendations of the Task Force have been approved by the Council of Ministers.

The 'ICT in Schools' scheme is a window of opportunity to the learners in the schools of India to bridge this digital divide. The scheme is not a simple merger of the earlier CLASS and ET Schemes but is a comprehensive and well thought-out initiative to open new vistas of learning and to provide a level playing field to school students, whether in rural areas or in the metropolitan cities. The 'ICT in Schools' Scheme is not a stand-alone scheme but actively solicits the partnership of States, Union Territories & other organizations in a mutual endeavour to bridge the heterogeneous proliferation of ICT across different socio-economic and geographic segments in the country. This partnership is manifest in the structure of financing the initiative, in encouraging the development of long-term Computer Education Plans, the setting-up of Smart Schools by KVS/NVS in State as technology demonstrators and in providing for supplementing the States efforts in these areas with no attempt being made to supplant the State Schemes.

The Centrally sponsored scheme of 'Educational Technology' and 'Computer Literacy and Studies in Schools' have been suitably modified keeping in view the past experience, the feedback which has been received and changing needs to form the new scheme of 'Information and Communication Technology in Schools'. The component regarding financial assistance to States/UT's for purchase of RCCPs and CTVs under the erstwhile Educational Technology Scheme has been weeded out.

OBJECTIVES

- (1) To establish an enabling environment to promote the usage of ICT especially in Higher Secondary Government Schools in rural areas. Critical factors of such an enabling environment include widespread availability of access devices, connectivity to the Internet and promotion of ICT literacy.
- (2) To ensure the availability of quality content on-line and through access devices both in the private sector and by SIETs.
- (3) Enrichment of existing curriculum and pedagogy by employing ICT tools for teaching and learning.
- (4) To enable students to acquire skills needed for the Digital world for higher studies and gainful employment.
- (5) To provide an effective learning environment for children with special needs through ICT tools.
- (6) Promote critical thinking and analytical skills by developing self-learning. This shall transform the classroom environment from teacher-centric to student-centric learning.
- (7) To promote the use of ICT tools in distance education including the employment of audio-visual medium and satellite-based devices.

DETAILS OF THE SCHEME

COMPONENTS

The present scheme has essentially four components. The first one is the partnership with State Government and Union Territories Administrations' for providing computer-aided education to Secondary & Higher Secondary Government Schools. The second is the establishment of SMART schools which shall be technology demonstrators. Universalisation of Computer Literacy through the network of KVS and NVS to neighbouring schools in the third component. The fourth component relates to the activities of SIETs.

IMPLEMENTATION PARTERS

States/UT Government, State Institutes of Education Technology, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Navodaya Vidhyalaya Samiti, Government and Government aided schools systems. Moreover, financial assistance would also be provided to short-listed NGOs/Trusts/Societies and Companies for software development, teaching tools, designing training models, evaluation, monitoring and other contingent expenditure. The State/UT Governments shall be free to partner with private organizations or integrate it with other similar schemes for implementation of the 'ICT in schools' Scheme including providing for maintenance. The implementation of the scheme will be multi-modal. The Ministry of Human Resource Development, shall consider the entry of the private sector in a Build-own-operate or annuity modal wherever possible. The direct procurement of hardware by the state would be the last resort. The National Council for Teachers Education shall be associated with the scheme in the context of training of teachers in computer aided learning. The Rehabilitation Council of India would play an important role in projects involving introduction of use of technology for the education of Children with special needs.

FINANCIAL PARAMETERS

(a) Under the CLASS component of the ICT scheme, the Union Government would provide 75% of financial assistance to State/UTs. The balance 25% of funds would be contributed by the State Government/UTs. The scheme also provides for contribution of 25% of funds from the MPLAD Scheme in addition or as an alternative to State Government Contribution. Assistance shall be provided to special category states in the ratio 90:10. The assistance of the Government of India would be for the following items and upto the limits indicated against each item.

1. 10 PCs/Printer/CRT per schools inclusive of facilities like scanner, web camera, mouse etc. or one server with 10 workstation with accessories.	-	4,05,000
2. Operating System & Application Software	-	20,000
3. Educational Software	-	45,000
4. Furniture	-	16,000
5. Computer Stationery	-	50,000
6. Teachers' Training	-	60,000
7. Internet	-	30,000
8. Maintenance- 50% of the cost of annual maintenance contract	-	20,000
9. Monitoring Cost	-	24,000
Total	-	6,70,000
10. Recurring Cost, which includes consumable, hardware and network maintenance, monitoring costs, telephone for Internet usage	-	1,34,000

It may be noted that even in the revised norms, it is proposed to have greater in-built flexibility. The States would have the option to incur expenditure on the above items or any other item like generators, preparation of labs for computers including civil repairs and cabling and provision of electricity depending upon their needs and resources. subject to a overall maximum limit of Rs. 6.70 lakhs per school. The Central Government's share would be restricted to Rs. 5.00 lakhs per schools.

The provision for software shall include Learning Management systems & curriculum based courseware apart operating systems & other application software.

An amount of Rs. 1 crore would be kept aside annually for the Department of Secondary and Higher Education for development of software, teaching tools, designing training models, evaluation, monitoring and other contingent expenditure.

Ministry of Human Resource Development shall endeavour to institutionalise content development through National education portal. The British Educational Communications & Technology, Agency (BECTA), UK could be considered as a modal incorporating elements of public private partnership.

KVS and NVS would convert one school per State/UT in to SMART school subject to availability of funds. A grant of not more than Rs. 25 lakhs would be given per SMART school. This limit may be reviewed in the future in needed. A sum of Rs. 2.5 lakhs shall be provided as recurring costs which includes maintenance, consumable, Internet usage & monitoring costs..

In SMART schools the emphasis would not only be on the use of Information Technology but also on the use of skills and values that will be important in the next millennium. It is hoped that at least one section (of 40 students) in each of the class IX- XII will be fully computerized. Thus a school having 160 computers @ 40 computer for each IX to XII classes may be called a SMART schools under the scheme. However, keeping in view the fact that this target cannot be achieved in one go, it is proposed to provide 40 computers to such identified schools. A grant of not more than 25 lakhs per schools would be given of KVS/NVS for the purpose.

Both KVS and NVS have indentified the schools which will be converted into a SMART school.

Kendriya Vidyalayas and Navodaya would be given funds at the rate of Rs. 20,000/- per neighbourhood school to impart computer literacy to not more than ten neighbourhood schools within a radius of 3 to 4 kilometers to cover 8,000 such schools over 3 years. The course shall be imparted in the local language if such a demand is recived from the beneficiary school. An Aadvisory committee consisting of the Principal of the Mother school and all Principals of participating schools will manage and oversee the programme.

The financial assistance to SIETs shall be in the project mode. The financial assistance would be provided to SIETs on the basis of the project proposals submitted by SIETs. These project proposals shall be submitted to the Project Monitoring and Evaluation Group which shall assess to the proposals submitted as to their utility and quality. Progressively, the administrative expenses of SIETs shall be reduced to zero within five years.

ILLUSTRATIVE LIST OF ACTIVITIES

- > Production of Audio, Video and Multi Media Programmes in the project mode by the State Institutes of Educational Technology established at Pune, Bhubaneswar, Patna, Luchnow, Hyderabad, Ahmedabad and Thiruvananthapuram.
- > Assessment of need for multi-media Programmes, preparation of profiles of target groups, design and development of audio-video programmes and other teaching aids, training of State level personnel in the process of educational technology viz. scripting, production of programmes and technical operations of equipment and studios for their production by Central Institute of Education Technology (CIET) State Institutes of Education Technology (SIET).
- > Training to teachers and teacher trainers in the production of low-cost audiovisual aids, help in script development, media production, editing, communication reserch, setting up and operation of audio and video studios and computerization of its various processes by Central Institute of Education Technology (CIET)/ State Institutes of Education Technology (SIET).
- > Feeding telecast and broadcast service titled Trarang and Umang respectively on DD-i and AIR and dedicated educational channel Gyan Darshan and Gyan Vani by CIET and SIETs.
- > Coordination of academic production and technical activities of the 6 State Institutes of Educational Technologies by CIET.

- > Organising educational Film Festivals/Multimedia contests.
- > Financial support to States/UTs on the basis of their Computer Education plans (CEPs).
- > Support to KVS/NVS for opening of SMART schools and for imparting computer literacy to students in neighbourhood schools.
- > Development of multimedia content for use in schools.
- > Digitisation of video and audio cassetters produced by SIETs on the basis of fresh assessment and in partnership with non-governmental agencies so as to make them viable and self-sufficient.
- > Establishing and Conferring National Awards for development and use of ICT tools.
- > Development of teaching tools, designing training modules for teacher.
- > Financial support for conversion of content into regional languages.
- > Projects for introduction of use of technology for the education of children with special needs.
- > Sale of audio and video Programmes made by SIETs on a commercial basis.
- > Leasing/hiring of studios and equipment by SIETs to other agencies both Government and non-Government on a commercial basis.
- > Training of teachers and master trainers / resource persons in the use of ICT tools for enrichment of curriculum and pedagogy.

PROCESS OF EXECUTION

Each State / UT would formulate a computer Education Plan (CEP). The CEP would indicate the steps already taken by the State Government/UTs and the assistance, which they now require. The project Proposals should inter-alia indicate number of schools in the state (government , government aided), the number already having computers, the number of schools now proposed to be covered and within what period, number of students likely to be benefited, whether state Government/UTs have made provision for the States share in their budget, vendors which have been short listed for procurement of equipment, provision of training, availability of infrastructure etc. While preparing the CEP, the State Government/UT will ensure that atleast two schools are selected from each identified Educationally Backward Block for assistance under this scheme.

The proposals for the existing components must indicate the funds received earlier for them, the status of their utilisation and benefits accrued in qualitative and quantitative sense.

Efforts would be made for convergence and dovetailing with schemes of other Department like Ministry of Information Technology whose representative will be invited to the meeting of the Project Monitoring and Evaluation Group. The States/Uts shall be free to dovetail this scheme with existing or proposed schemes of the State Governments.

Funds will allotted to KVS/NVS for SMART Schools and Universalisation of Computer Literacy on the basis of the proposals submitted by KVS/NVS.

The Department of Information Technology would contribute to the scheme by making available its infrastructure resources and expertise to provide internet connectivity to schools.

The GIAS shall be empowered to effect modifications in the scheme based on the feedback received and depending upon changes in the technological environment. As the shift in technological parameters in rapid, this would ensure that the scheme is able to adapt itself to changing conditions and requirements. Financial norms and budgetary outlays shall, however, be strictly adhered to.

GRANT-IN-AID COMMITTEE

A Project Monitoring and Evaluation Group headed by the Secretary (Secondary and Higher Education) would consider the Computer Education Plans (CEPs) received from the States/UTs. The Committee would also include a representative of Ministry of Information Technology, NIC and representatives of organizations engaged in the field of computer education. This Group shall also consider the project proposals submitted by SIETs.

RELEASE OF GRANT

On approval of the project/CEP the grant shall be released to the State/UT/SIET on an annual basis in two or more installements-the first installment of 50% will be released immediately after the issue of sanction. After the State/SIET has utilized 75% of the 1st installment it may make a request for release of the subsequent installment along with progress report and statement of expenditure with full details. The release of grants in the second and subsequent years will be made on similar basis, provided that before release of the second installment in a particular financial year (beginning with the second year) the utilization certificate and audited statement of accounts in respect of grants released till the end of the proceeding year shall be furnished.

DISBURSEMENT

The grants of SIETs/KVS/NVS would be remitted either by Demand Draft drawn in its favour by the Ministry of Human Resource Development or by telegraphic transfer to the savings bank account opened in its name. The grants to States/UTs would be given through Inter Government adjustment advice.

MONITORING AND EVALUATION

The Project Monitoring and Evaluation Group would also function as the Monitoring Committee. In addition, the SIETs and the State/UT Government submitting the proposal would be required to submit progress reports every quarter. The Department would also explore the possibility of getting the 'ICT in Schools' scheme evaluated through an independent agency.

ANTICIPATED OUTCOMES

1. The Scheme shall enable the widespread use of ICT in schools during the 10th Plan period leading to enrichment of existing curriculum and pedagogy.
2. The scheme shall enable the students to acquire necessary skills needed for both higher education and for gainful employment.
3. During the 10th Plan period a total number of 9380 schools shall be covered for employment of ICT tools.
4. Efforts shall be made to ensure coverage of the scheme in all States and Union Territories of the country during the 10th Plan.
5. A system of hosting and accessing quality educational content on a nationwide basis shall be established. This shall be available online as well as through other access devices.
6. Two SMART schools shall be established in each State and Union Territory by KVS/ NVS, which shall serve as technology demonstrators,
7. KVS and NVS shall operationalise the component relating to Universalisation of Computer Literacy and shall cover a minimum of 8,000 schools.
8. Projects to introduce the use of technology for the education of children with special needs shall be established
9. State Institutes of Education Technology shall become substantially self-financing.
10. Each SIET shall produce and transmit at least 200 programmes each year.

“परिशिष्ट-तीन”
मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्र/एफ 44-15/2005/20-2

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

म. प्र. के कतिपय स्कूलों में Information & Communication Technology @ Schools (ICT) योजना लागू करने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समन्वय समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|----|--|---|------------|
| 1. | जिला कलेक्टर | - | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत | - | सदस्य सचिव |
| 3. | नगर निगम आयुक्त/सी.एम.ओ. नगर पालिका | - | सदस्य |
| 4. | जिला शिक्षा अधिकारी | - | सदस्य |
| 5. | सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग | - | सदस्य |
| 6. | योजना संचालित शाला के कलेक्टर द्वारा नामांकित दो प्राचार्य | - | सदस्य |
| 7. | कलेक्टर द्वारा नामांकित दो कम्प्यूटर विशेषज्ञ | - | सदस्य |
2. समिति का निम्नानुसार कार्य होगा —
1. जिला स्तर पर योजना का समग्र रूप से कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण.
 2. राज्य शासन द्वारा निर्धारित कान्फिग्रेशन अनुसार जि चयनित स्कूलों हेतु कम्प्यूटर एवं उपकरणों का क्रय करना.
 3. योजना संचालन हेतु राज्य समिति के दिशा निर्देश के तहत जिले के विद्यालय का चयन करना) जिसमें जिले के सभी विकास खण्डों के स्कूल आफ एक्सीलेंसी नीतिगत रूप से सम्मिलित किया जायेगा.
 4. कम्प्यूटर लेब हेतु स्थल का चयन एवं निर्माण
 5. जिला स्तर पर शुल्क का निर्धारण करना
 6. जनभागीदारी एवं एम.पी./एम.एल.ए. निधि से स्थानीय स्तर पर राशि समिति की व्यवस्था करना.
 7. शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में निजी निवेशकों की भागीदारी से कम्प्यूटर योजना प्रारंभ करने हेतु निजी निवेशकों का चयन करना.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
आर. बी. सावनेर
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पु. क्र/एफ 44-15/20-2-2005

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

प्रतिलिपि :-

- (1) समस्त कलेक्टर (म. प्र.)
- (2) आयुक्त लोक शिक्षा, म. प्र. भोपाल
- (3) संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म. प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ.

हस्ता./-
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

परिशिष्ट - 1

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एच 44-15/2005/20-2

भोपाल, दिनांक 10-10-2005

म0प्र0 के कतिपय स्कूलों में Information & Communication Technology @ School (ICT) योजना लागू करने हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार समन्वय समिति का गठन किया जाता है:-

- 1- जिला क्लेक्टर - अध्यक्ष
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत - सदस्य सचिव
- 3- नगर निगम आयुक्त/सी0एम0ओ0
नगर पालिका - सदस्य
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- 5- सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
विभाग - सदस्य
- 6- योजना संचालित शाला के क्लेक्टर
द्वारा नामांकित दो प्राचार्य - सदस्य
- 7- क्लेक्टर द्वारा नामांकित दो कम्प्यूटर
विशेषज्ञ - सदस्य

2/- समिति का निम्नानुसार कार्य होगा-

- 1- जिला स्तर पर योजना का समग्र रूपसे कार्यान्वयन एवं अनुभव
- 2- राज्य शासन द्वारा निर्धारित कार्यान्वयन अनुसार जिले वर्गान्त स्कूलों हेतु कम्प्यूटर एवं उपकरणों का क्रय करना।
- 3- योजना संचालन हेतु राज्य समिति के दिशा निर्देश के तहत जिले के विद्यालयों का चयन करना जिसमें जिले के सभी विकास ब्लॉकों के स्कूल अथवा समीक्षित स्तरों के स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल किए जायेंगे।
- 4- कम्प्यूटर लेष हेतु स्थल का चयन एवं निर्माण
- 5- जिला स्तर पर शुल्क का निर्धारण करना
- 6- जनभागीदारी एवं एम0पी/एम0एल0ए0नाधि से स्थानीय स्तर पर राशि संग्रहण की व्यवस्था करना।
- 7- शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में निजी निवेशकों की भागीदारी से कम्प्यूटर योजना प्रारंभ करने हेतु निजी निवेशकों का चयन करना

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार
7-10-05
आर0बी0 सचिव
अवर सचिव

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

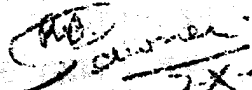
//2//

पु0क0/ सव 44-15/20-2/2005

भोपाल, दिनांक 10-10-2005

प्रतिलिपि:-

- १११ समस्त कलेक्टर १ म0प्र0१
 - १२१ आयुक्त लोक शिक्षण, म0प्र0भोपाल
 - १३१ संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र म0प्र0भोपाल
- की और सूचनार्थ ।


अवर सचिव 7X-05

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग